



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63357

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 12229 वर्ष 2026

दिनेश चौरसिया

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	सर्वानन्द पांडे
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता; राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. प्रस्तुत 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, महाराजगंज के न्यायालय में लंबित परिवाद प्रकरण संख्या 466 वर्ष 2022, (मनोरमा देवी बनाम दिनेश) अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, पुलिस- स्टेशन- फरेन्दा, जिला- महाराजगंज में पारित समन आदेश दिनांक 17.01.2023 के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोनों पक्षों के बीच धन का विवाद है और प्रतिपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दर्ज कराई है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि चूंकि धन के भुगतान को लेकर विवाद है, इसलिए आपसी समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रबल संभावना है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., 2010 (5)**



एससीसी 663 में प्रतिवेदित किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है। प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

“17. हाल ही में प्रकाशित एक टीका में, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नानुसार संप्रेक्षण किए गए हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम के विषय पर विधि सुधारों के संबंध में कुछ विचार - वादों के हिमस्खलन से निपटना] (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर] :

“....अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ (परिवादी के संदर्भ में) दंड प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन की वसूली सुनिश्चित करने का साधन है। परिवादी का हित मुख्य रूप से चेक जारीकर्ता को जेल भेजने की बजाय धन की वसूली में निहित है। जेल की धमकी मात्र वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। जहाँ तक अभियुक्त के जेल जाने की इच्छा का प्रश्न है, चेक धारक के पास उपाय के रूप में बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं।

यदि हम एक पक्ष के अंतिम निर्णय से पहले 'समझौते' या 'निपटान' किए गए परिवादों की संख्या और दूसरे पक्ष के उन मामलों की जांच करें जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचें, तो हम पाएंगे कि अधिकांश मामले सुलझा लिए गए और केवल नगण्य संख्या में मामले ही आगे बढ़ें।“

18. यह स्पष्ट है कि चेक के अनादरण के अपराध के संबंध में, दंडात्मक पहलू की तुलना में क्षतिपूर्ति पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को भी कुछ हद तक समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामले वास्तव में समझौते या सुलह के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में, जिससे न्याय मिलने में अनावश्यक देरी हो रही है। समस्या यह है कि वादीगण अपने विवाद को सुलझाने के साधन के रूप में देर से सुलह का विकल्प चुनते हैं।.....

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान अटॉर्नी जनरल का कहना है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार परिवाद का संज्ञान लेते ही समझौता करने के बजाय अंतिम उपाय के रूप में समझौता करना चुन रहे हैं। ऐसे व्यवहार का एक कारण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार हैं और समझौता तभी चुनते हैं जब कोई अन्य रास्ता न बचे। हालांकि मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से ऐसा व्यवहार तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समझौता करने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ाती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के चरण में समझौते के माध्यम से अपराध का निपटारा या समझौता करने को तैयार है, तो यह आमतौर पर परिवादी के मामले में कुछ सच्चाई का संकेत होता है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों में ही समझौता करना चुनें। हालांकि, यदि अभियुक्त के पास गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसे वैध बचाव हैं, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है।"

5. अधिवक्ता के अनुरोध पर, यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने के भीतर अपने प्रतिनिधि अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और समझौता करके अपराध के शमन के लिए आवेदन प्रस्तुत करे तथा चेक राशि का 10% जमा करे। ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगा और अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार महीने की अवधि तक का और अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद, न्यायालय **दामोदर एस. प्रभु** (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आज से पांच महीने की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होना और विचारण का सामना करना आवश्यक होगा और न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने और कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

7. उपर्युक्त पांच महीने की अवधि के दौरान या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी उत्पीड़नात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से यह आवेदन इस न्यायालय में दायर किया गया है।

9. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ इस आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

26 मार्च, 2026

मीनू सिंह